यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/94/2018 **दिनांक :** 07.08.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

देना बैंक की परिस्थितियाँ

जैसा कि हमने आपको अपने विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से अवगत कराया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने देना बैंक पर सभी तरह के ऋण देने और बैंक में किसी भी नई भर्ती पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इस तरह देना बैंक को समाप्त किए जाने के प्रयास हैं। अभी हाल ही में वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में एआईबीईए–एआईबीओए ने देना बैंक पर से प्रतिबंध हटाने की माँग करते हुए उन्हें अपना स्मरण पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस विषय में एआईबीईए–एआईबीओए द्वारा जारी संयुक्त परिपत्र संख्या 2018/7 दिनांक 7.8.2018 का अनूदित सार आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

देना बैंक पर से अवरोध को हटायें

3 अगस्त, 2018 को, साथी डी. राजा, सांसद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया के साथ, हम वर्तमान वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल से मिले और ऋण स्वीकृत करने से देना बैंक पर आरबीआई के प्रतिबंध को वापस लेने की हमारी माँग पर उन्हें स्मरण पत्र प्रस्तुत किया। हमने उन्हें बताया कि आरबीआई का यह निर्देश अनुचित है क्योंकि अन्य 10 बैंकों के साथ देना बैंक पहले से ही पीसीए मानदंडों के तहत है और ये कठोर प्रतिबंध बैंक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं। उनका भी यह मत था कि इस मामले को आरबीआई द्वारा समीक्षा की जरूरत है। हम अब आरबीआई के साथ इस मामले को उठायेंगे।

अभिवादन सहित,

आपके साथी,

ह0...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री
एआईबीईए

ह0...
एस. नागराजन
महामंत्री
एआईबीओए

जारी पृष्ठ 2

एआईबीईए–एआईबीओए / पत्र / 2018 / 6 3.8.2018

सेवा में माननीय वित्त मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली

प्रिय महोदय,

विषय : देना बैंक द्वारा ऋण देने पर से अवरोध को हटाना

आप कृपया इस बात से अवगत होंगे कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने देना बैंक को निर्देश भेजे हैं जिसमें बैंक द्वारा सभी ऋण देने और किसी भी ऋण की मंजूरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

अन्य सभी बैंकों की तरह, देना बैंक भी खराब ऋणों के उच्च स्तर, कम आय और परिणामस्वरूप उच्चतर प्रावधानों और शुद्ध हानि की समस्याओं का सामना कर रहा है। लेकिन देना बैंक ने सभी वर्षों में परिचालन लाभ अर्जित किया है।

ऐसे 11 बैंक हैं जो वर्तमान में आरबीआई के पीसीए मानदंडों के तहत हैं और देना बैंक उनमें से एक है। देना बैंक के बारे में विशेष रूप से चिंताजनक कुछ भी नहीं है और प्रबंधन के साथ–साथ सम्पूर्ण कार्यबल बैंक के बेहतर स्वास्थ्य को वापस लाने के कार्य में लगा है।

बैंक, यूनियनों तथा सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में, बैंक के उच्च कार्य निष्पादन की ओर मोड़ने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

बैंक के वित्तीय प्रदर्शन पर निम्नलिखित आंकड़े बतायेंगे कि बैंक लगातार परिचालन लाभ अर्जित कर रहा है।

रू करोड़ में

	परिचालन लाभ	प्रावधान	शुद्ध लाभ / शुद्ध हानि
मार्च 2010	840	329	+ 511
मार्च 2011	1,223	612	+ 611
मार्च 2012	1,528	725	+ 803
मार्च 2013	1,739	929	+ 810
मार्च 2014	1,774	1,222	+ 552
मार्च 2015	1,330	1,065	+ 265
मार्च 2016	925	1,860	- 935
मार्च 2017	1,390	2,254	- 864
मार्च 2018	1,170	3,093	- 1,923

इस तरह, यह अनुभव किया जा सकता है कि परिचालन लाभ के मामले में बैंक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और केवल बढ़ते हुए खराब ऋणों के कारण, मुनाफा कम हो गया है।

देना बैंक पर लगभग रू0 16,500 करोड़ के खराब ऋणों का बोझ है। निम्नलिखित आंकड़े बतायेंगे कि मुख्य दोषी कौन है।

कुल खराब ऋण / एनपीए	16,500 करोड़	
250 बड़े उधार अदा न करने वालों के खराब ऋण	13,000 करोड़	80%
1,25,000 छोटे उधार अदा न करने वालों से देय राशि	3,500 करोड़	20%

जारी पृष्ठ 3

इस तरह, यह अनुभव किया जा सकता है मुख्य दोषी बड़े उधार अदा न करने वाले हैं। इन प्रमुख जानबूझकर उधार अदा न करने वालों को दंडित करने के बजाय, बैंक और इसके कार्यबल को सजा दी जा रही है।

इस मौके पर, आरबीआई ने बैंक के ऋण देने पर पूर्ण रोक लगा दी है जिसके द्वारा बैंक द्वारा किसी ऋण को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। यह बैंक को गंभीर रूप से आघात पहुंचायेगा यदि यह जारी रहता है तो। गुजरात, महाराष्ट्र जैसे देश के कई हिस्सों में देना बैंक एक महत्वपूर्ण बैंक है।

उन पर मुख्य जिम्मेदारियां हैं और सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के रूप में, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने का देना बैंक का दायित्व है। इस प्रतिबंध द्वारा, कृषि क्षेत्र, छोटे तथा मध्यम उद्योगों, शिक्षा ऋण, खुदरा ऋण, मुद्रा लोन, इत्यादि को भी सभी उधार रोक दिए गए हैं।

बैंक को इसके सामान्य स्वास्थ्य में वापस लाने के लिए खराब ऋणों को वसूल करने, फजूलखर्चों को कम करने, ब्याज आय और अन्य राजस्व बढ़ाने, पूंजी को संरक्षित रखने की आवश्यकता है। बैंक को अपंग बनाना समाधान नहीं है, बल्कि यह आत्मघाती होगा। जब सभी बैंक समान समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे निर्देशों और कठोर उपायों के साथ देना बैंक को अलग करना उचित नहीं है।

कोई भी उच्च मूल्य जमाराशियों को गिराने और कम लागत अग्रिमों को हतोत्साहित करना समझ सकता है। कोई भी बड़े ऋणों की मंजूरी में कुछ सतर्कता को समझ सकता है। लेकिन क्या कोई बैंक बिल्कुल उधार देना टाल सकता है ? क्या एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण रोक सकता है और सामाजिक ऋण देना रोक सकता है अथवा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर भाग सकता है ?

आरबीआई के निर्देश के नाम पर, अंधाधुंध शाखा बन्दी के प्रयास हैं। यहाँ तक कि लाभ कमाने वाली शाखाओं को भी बंद करने के प्रयास हैं। हम अलाभकारी शाखाओं के विलय अथवा बेहतर स्थानों पर शाखाओं के स्थानांतरण को समझ सकते हैं। लेकिन हम बड़े पैमाने पर शाखाओं की बन्दी के लिए सहमत नहीं हो सकते क्योंकि शाखायें किसी भी बैंक के लिए व्यवसायिक स्थल और लाभ का केन्द्र हैं।

इसी प्रकार, पर्याप्त श्रमशक्ति व्यवसाय के विकास के लिए एक पूर्व–आवश्यकता है। पहले से ही कर्मचारी और अधिकारी बैंक के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं और बैंक का बेहतर स्वास्थ्य बहाल करने के लिए सभी उपायों में और अधिक सहयोग देने के इच्छुक हैं। लेकिन भर्ती पर प्रतिबंध के माध्यम से कार्यबल को निरूत्साहित किया जा रहा है और यहां तक कि अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों पर भी रोक लगाई जा रही है। पर्याप्त कर्मचारियों के बिना, पुनरूद्धार रणनीतियों को कौन लागू करेगा ?

हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि देना बैंक को अलग किया जा रहा है जबकि बैंक द्वारा सामना की जाने वाली समस्यायें कई अन्य बैंकों की समस्याओं के समान ही हैं।

महोदय, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आरबीआई को उनके भेदभावपूर्ण निर्देश पर पुर्नविचार करने और बैंक द्वारा ऋण देने पर से अवरोध तथा अन्य प्रतिबंधों को वापस लेने की सलाह दें।

सधन्यवाद,

आपके विश्वासपात्र,

ह0...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

ह0...
एस. नागराजन
महामंत्री